

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table of the House.

**MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.**

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI):** Shri Maheshwar Singh. Only two minutes left for your party.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) महोदय, अगर ऐसी बात है तो मैं बिन बोले ही बैठ जाता हूँ।

**THE VICE-CHAIRMAN (Shri Ajit P.K. Jogi):** I am telling you in the beginning itself that you will have to be very brief.

श्री महेश्वर सिंह: एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा महोदय, जब पार्टी में पहले ही पांच नाम थे तो समय का विभाजन पहले से ही ठीक रखना चाहिए था।

**THE VICE-CHAIRMAN (Shri Ajit P.K. Jogi):** You know the procedure. Do not take much time...(Interruptions) ...It is within your party.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण संसद के समक्ष महासहिम राष्ट्रपति जी ने 20 फरवरी को दिया, उसके संदर्भ में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को सुनते-सुनते सात वर्ष हो गए हैं, लेकिन ऐसा नीरस और दिशाहीन अभिभाषण पहले कभी सुनने को नहीं मिला और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि आधे से ज्यादा माननीय सदस्य वहाँ सो रहे थे।

महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको और माननीय सदन का ध्यान अनुच्छेद 5 की ओर ले जाना चाहूंगा जहाँ महासहिम राष्ट्रपति ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का, विशेषकर राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित करने का उल्लेख किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन साथ ही साथ उन प्रान्तों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, इस देश के कई पहाड़ी राज्य आते हैं और हिमाचल भी उसमें आता है। ये ऐसे प्रान्त हैं जिनका अपना विशेष कोई आब का स्रोत नहीं है और वे केन्द्र की आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं। पहले इन प्रान्तों का जितना भी डेफिफिस्ट होता था, उसको राइट आफ कर दिया जाता था, यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहलाते थे। मुझे खेद है कि 9 में फाइनेंस कमिशन के समक्ष, हो सकता है कि उस वक्त की इन प्रान्तों की सरकारों अपना पक्ष ठीक से नहीं

रख सकी हों और उसके बाद एक कट लग गया है और आज ये सारे के सारे पहाड़ी प्रान्त, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, एक आर्थिक संकट से घिरा हुआ है और उसका आज आर्थिक संकट से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ ऐसे प्रान्त भी हैं जो अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं लग रही है। अब ऐसे प्रान्तों को, जो आर्थिक संकट में हैं, आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकाला जाए? इस बारे में भी राष्ट्रपति महोदय का यह अभिभाषण मौन है। यहाँ जब बिहार के बारे में कल भेरे दल के एक सदस्य बोल रहे थे तो उधर से बहुत टीका-टिप्पणी हो रही थी। मैं बिहार के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उस सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है (व्यवधान) अरे भाई मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ (व्यवधान)

श्री नरेश यादव (बिहार): आप राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोले बिहार बीच में कहाँ से आ गया?

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आप अपनी बात जितनी संक्षिप्त और जल्दी कर सकें, करें।

श्री महेश्वर सिंह: मैं अपने प्रान्त की बात भी कहूंगा। महोदय, मैं बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि जिस प्रान्त में सांड स्कूटर पर जा सकता है, उस प्रान्त के बारे में बात क्या करनी है। यहाँ चार घोटाले की बात आई, जिस समय वहाँ नरल सुधार के लिए सांड गांव को भेजे गए, तो उसमें जिन गड़ियों के नम्बर सामने आए, उसमें एक स्कूटर का नम्बर भी आया।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI):** Your party's time is up. Pleased try to conclude.

श्री महेश्वर सिंह: महोदय इसमें सिर्फ इनकी मोनोपली नहीं है, हिमाचल भी पीछे नहीं है। बाकी जगह तो दलाली ली जाती है लेकिन हिमाचल सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने एक रिजर्व क्वॉटम कर दिया कि उसने कर्जा लेने के लिए दलाली दी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट में आया है। इससे बड़ी वित्तीय अनुशासनहीनता क्या होगी कि एक सरकार, जो वहाँ चंडीगढ़ और दूसरे स्थानों पर निजी फाइनेंशियल कंपनियों बैठी हैं, वह कर्जा लेने के लिए उनको एक परसेंट दलाली देती है 300 करोड़ का कर्जा लेती है और 3 करोड़ दलाली देती है। ऐसी सरकार आज हिमाचल में चल रही है। मैं माननीय सदन के माध्यम से यह ध्वज

करना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को, जो वित्तीय अनुशासनहीनता करती है, उसके भंग किया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी):** महेश्वर जी, अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री महेश्वर सिंह:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू में ही निवेदन किया था कि अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ।

4.00 P.M.

महोदय, इसके बाद मैं सदन का ध्यान अभिभाषण के अनुच्छेद 16 की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ विद्युत उत्पादन की बात कही गई है। मैं पूर्व गृह मंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि आज बिजली एक ऐसी जीव है जो कि किसी भी देश के लिए आर्थिक आधार है। उसका डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। महोदय, हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा प्रान्त है जो आज 20,000 मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। प्रकृति ने हमको पानी ऐसा दिया है जो बिजली पैदा कर सकता है। प्राकृति ने हमको पत्थर ऐसा दिया है जो सीमेंट बना सकता है। सौर्य ऐश दिया है जिसे देश और विदेश के पर्यटक देखने के लिए आते हैं। लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए हमें पैसा नहीं मिलता। हमारे पास ऐसी-ऐसी परियोजनाएँ हैं जो कि उस प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकती हैं और देश को बिजली दे सकती हैं लेकिन इस और सरकार का ध्यान नहीं है।

महोदय मैं कई बार ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान में यह बात लाने की कोशिश की है कि वहाँ पर नाचवा पाकड़ी प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार के साथ ज्वाइंट वैंचर में चल रहा है लेकिन उसका दफ्तर आज भी भाई वीर सिंह मार्ग पर पैदा है। जब भी मैं पूछता हूँ तो मंत्री जी कहते हैं कि वह दफ्तर हिमाचल जा चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं गया है। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि जिस सपरियोजना का दफ्तर दिल्ली में हो उसका आफिसर दिल्ली में एयर कंडीशंड कमरे में बैठा हो तो उस परियोजना का काम कैसे चल सकता है? मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि हिमाचल में जितनी भी परियोजनाएँ चल रही हैं। उनके लिए अधिक से अधिक धन दिया जाए।

महोदय चक्राण साहब ने ट्रांसमिशन लासेज की बात भी कही थी महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लासेज पहाड़ों में ज्यादा होते हैं। इसलिए जो सिस्टम इंपूर्वमेंट स्कीम वहाँ से आती है, उन पर

जल्दी से जल्दी आर०ई०सी० को सहमति देनी चाहिए ताकि ये ट्रांसमिशन लासेज कम हो सके (समय की घंटी)

महोदय चूँकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए अंत में मैं अभिभाषण के अनुच्छेद 25 की ओर आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूँ जिसमें मध्याह्न भोजन की बात कही गई है जिसका उल्लेख हमारे साथी बेबी साहब ने भी किया है। महोदय, ऐसी योजना का मैं विरोध करना चाहता हूँ। महोदय, आज खैरत बांटने की जरूरत नहीं है। इस योजना का कितना दुरुपयोग हो रहा है, यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। महोदय इस योजना के हिसाब से 3 किलो राशन प्राप्त बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। आप स्वयं जातने हैं कि पहाड़ों में राशन की दुकानें नज़दीक नहीं हैं। करीब 3-3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्राथमिक कक्षाओं के बालक पूरा-पूरा दिन वहाँ किचो में बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पूरा राशन नहीं मिलता। आप इसकी छानबीन करा लीजिए कि उन्हें 3 किलो राशन मिल रहा है या नहीं।

महोदय, आज आवश्यकता है शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की। महोदय, कैसे वे स्कूल चल सकते हैं जहाँ 5 कक्षाएँ बैठी हों और एक ही अध्यापक उन्हें पढ़ाता हो। जब एक माँ 3 बच्चों को नहीं संभाल सकती है तो एक अध्यापक 5 कक्षाओं को कैसे संभाल सकता है?

**उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी):** आप फिर नए विषय पर आ गए। आपने कहा था आप समाप्त कर रहे हैं।

**श्री महेश्वर सिंह:** महोदय, मैं इसी विषय पर बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। महोदय, मैं जवाहर रोज़गार योजना की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे वहाँ जितनी भी योजनाएँ जिला स्तर पर चलती हैं उनमें सांसद को कभी विश्वास में नहीं लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ कि केन्द्र की सहायता से जितनी भी योजनाएँ चलती हैं, उनमें सांसद अध्यक्ष होना चाहिए। ताकि उनकी समीक्षा की जा सके। श्रंतीय सरकार कोशिश यह करती है कि उसका श्रेय वह खुद ले ले। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि जब हम वहाँ सत्र में होते हैं, तभी वे मीटिंगें करते हैं ताकि हम उनमें उपस्थित न रह सकें।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के बिना पहाड़ों में सड़कें नहीं बन सकती हैं। अगर आप जवाहर रोज़गार योजना के

अंतर्गत सड़के बनाना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विस्फोटक पदार्थों की खरीद की अनुमति देनी होगी। यह अधिकार क्लकटर को दिया जाना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार वह विस्फोटक पदार्थ खरीद सके और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के बन सकें। महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, how much is my time?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): We have to conclude the discussion today by 5 o'clock, and there are about 10 speakers left.

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to know my party's time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): Your party has got about 15 minutes and three speakers.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will speak for about 15 minutes, if you permit me. There are three speakers. There are 50 minutes and, therefore, I will take 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): Your time is 15 minutes for three speakers. So you have five minutes if you want other speakers from your party to speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, then I will touch upon very important points only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): Brevity is the soul of wit!

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to support the motion moved by Shrimati Kamla Sinha thanking the President for his Address to both Houses of Parliament, and seconded by Shri Ramachandra Reddy.

Sir, traditionally, when we see the President's Address, it is a replica of the

previous year's Address. The stress on agriculture and industries will be there, then the rural poverty alleviation programmes, foreign affairs, education, health facilities and also the scientific research work. These will be the areas covered by the President.

Sir, various things have been mentioned here. The Employment Assurance Scheme is there, but I do not want to say much on this. The Mid-Day Meals Scheme is also there. Similarly, the schemes for self-employment are being strengthened. And the President was referring to these.

Sir, as far as employment to the people is concerned, the youth who are today taking to violence are doing so because they are not able to get employment both in the rural areas and the urban areas. We find that much needs to be done in this area. This is not a party affair. I would like to submit that according to the system which has been evolved, the State Government, under the schemes sponsored by the Central Government, select candidates for the purpose of providing them opportunities for self-employment, and then they refer the matter to the banks concerned for the purpose of giving them assistance. It is so in all the States; it is not confined to "X" State or "Y" State. But the banks are turning down 70 per cent of the applications that have been recommended for giving loans to the educated-unemployed or rural-unemployed. The President's Address says that there is a scheme for self-employment which has been strengthened by the Government. What is the scheme? How are they going to give employment to one million people as mentioned in the President's Address? It is very nebulous.

I saw the hon. Prime Minister talking about the price situation. He was passing the buck to the State Governments. He says that it is the State Governments which have to monitor the price situation. "We give them the required grains under the PDS but we cannot do anything on

this." The Central Government which has been giving the grains under the PDS is releasing the quotas, and the Central Government should have a monitoring mechanism to see whether the State Governments are implementing the scheme properly or not. I find that the Central Government cannot do it at the present juncture because of the 13-party coalition. If the Central Government puts any machinery for the purpose of checking whether the PDS is properly implemented by any State Government or not, or whether the price control mechanism is implemented or not, then one party or the other will withdraw its support to the present Government. Therefore, the Central Government will be a silent spectator, as stated by the hon. Prime Minister in this august House. The price situation is one thing which is today haunting the people of this country, whether they are the poorer sections of the society, the middle class, upper-middle class or the Government servants.

They are suffering because of the high rise in the prices of essential commodities and other items. They are feeling the pinch of a hundred per cent rise in the price of essential commodities and other items which they are using daily. They are not able to have some savings. Even the middle classes are not able to have some savings. But the Government is complacent. The Government is not taking any steps. It says that it is for the State Governments to take steps. Even when our Government was there, we were making pleas that there should be a monitoring mechanism so that the prices could be checked at every stage. Unfortunately, I feel that the present Government will not be able to control the price rise and that it is going to be a burden on the common man tomorrow, even after the presentation of the Budget.

The hon. Finance Minister has presented a sugar-quoted budget. When the Government goes to implement the Fifth Pay Commission recommendations and

when it goes to augment the Oil Pool Account, where will we reach? We will be able to do nothing. The State Governments also have to pay increased salaries to their employees on the basis of the Fifth Pay Commission recommendations. Rs. 85,000 crores is required. How are they going to augment the resources? I do not know whether the Government of India has got any plan for the purpose of meeting this expenditure in future. But the hon. Finance Minister has given several concessions in customs duties. The senior leader of our party, Mr. Pranab Mukherjee, has been putting it very candidly that the customs duties have been slashed to kill the local industry. This is becoming a very big issue today. The slashing of the customs duties will allow multinationals to come and dump their goods here. I do not know whether this is there in the Common Minimum Programme.

Then, another thing is about the insurance sector. Outside Parliament, hon. Members from the Left parties have been agitating against this. The Finance Minister is now slowly, in an indirect manner, bringing in the joint sector. Are you approving of it?

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): You will get our response during the Budget Discussion.

SHRI V. NARAYANASAMY: What about you Common Minimum Programme?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Will you please address the Chair? Please address the Chair. Please don't address the Member.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am not addressing the Member. Let the hon. Member not disturb me. Let him speak when his turn comes.

There is one yardstick here in this House, and there is another yardstick outside the House for the consumption of the cadres of their parties. Let them avoid that.

Because of the time-constraint, I am going to make a short speech.

A very important issue has appeared in today's newspapers. The hon. President has dilated very much on the issue of terrorism. Today, terrorism is on the rise in Jammu and Kashmir, Assam and the North-Eastern States. There is one item which refers to heroin and also RDX worth Rs. 100 crores, which was brought from abroad to Bombay. Nobody knows where it has gone. Who brought it to our country? This Government has to address itself to these things. We know the Bombay blast case. Some people were arrested. Something happened in Calcutta and Delhi also. The hon. Home Minister is sitting here. He knows pretty well that heroin and RDX worth Rs. 100 crores was smuggled into this country. Who were the persons behind it? Were any politicians involved in it? Were traditional criminals involved in it? The hon. Prime Minister, when he knows that it was smuggled in, has to inform this august body about the persons responsible for it. It is a very, very serious thing because thousands of lives were lost due to the bomb-blasts in Bombay. Blasts took place all over Bombay. It is happening in other States also. What strategy does the Government have to tackle this problem of terrorism? Similar incidents are happening in Jammu and Kashmir.

People have no security in Assam. People are losing faith in the State Government. The State Government blames the Central Government. The Chief Minister of Assam has said, "I wanted para-military forces. The Home Ministry has not given the required forces. Therefore, we are not able to tackle terrorism in Assam." This is what he has said. What is happening in Tripura? The people have no security of their lives in Tripura. There is a revolt by the people in Tripura. These issues have not been addressed. Only a general word about terrorism has been mentioned.

Sir, I have to make only two other points, and then I will conclude.

Another important issue is about sharing of waters by various State Governments. The disputes are pending for years together. Negotiations were held, commissions were appointed, but no fruitful results have come in. Today, fortunately for the Prime Minister, there is a 13-party coalition at the Centre and these coalition partners are ruling in various States. Why does the Central Government not talk to the concerned State Governments and resolve the issue, whether it is the Cauvery waters issue, or the Narmada waters issue, or the Krishna waters issue? Various issues are pending and the Government has not taken any step to resolve them. They appoint a commission. The commission goes into the matter and even after an interim award....

**SHRI NILOTPAL BASU:** Sir, if Mr. Narayanasamy yields, I would like to ask him a question.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI):** He has not yielded. Let him complete. You should appreciate that we have to complete the debate.

**SHRI NILOTPAL BASU:** You can add this to his time. There is no problem. I just want to put a question to him, through you.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI):** You ask the Home Minister. Why are you asking him?

**SHRI NILOTPAL BASU:** Because he is making a point.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** The Prime Minister is going to answer, I am not going to answer. Sir, I am making my points and the Prime Minister should reply to them.

**SHRI NILOTPAL BASU:** Sir, he is talking about reconciliation between two States. The two State units of the parties which he represents are reconciled on the issue of sharing of waters.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** Sir, there are various other States. Between Andhra and Karnataka there is the

Alamatti issue where you could not get it reconciled.

**SHRI NILOTPAL BASU:** When there were same parties in the two States, they could not reconcile it.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** The Alamatti issue came up very recently, about six months back. That came up because the Prime Minister allocated more funds to Karnataka. As a result Andhra revolted. So far as Cauvery issue is concerned, an interim award was given, but it was not implemented, because it was not notified. The Government of India is yet to notify the Interim Award. As a result they have to go to court again and again to get the of the Commission Award implemented. In the process the farmers are suffering. These inter-State issues have to be resolved by the Central Government, but it has not taken any step in this direction. The Prime Minister, hailing from Karnataka, is supporting the people of Karnataka and the interests of the people of Tamil Nadu are being overlooked. This is my point.

My last but one point is about the SC/ST and Backward Classes. There is a 27 per cent reservation for the Backward classes and 22.5 per cent for SC/STs. When I.A.S. or other Central Government examinations are held, reservation quota is to be given to the candidates who belong to these categories. The problem is when a candidate is selected on merit as a result of the competitive examination, that SC/ST or Backward Class candidate is brought into the SC/ST/Backward class reserved category and the 51 per cent reservation is given to other castes as the cost of the SC/ST/Backward Class candidates, who are to be appointed in the normal course. Why are they doing so? I have written several letters. I have talked to the Prime Minister even, but there is no positive response. In his Address, the President has said: "This Government is committed to the development of backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and minorities." That is what he said.

Are they doing it really? Hon. Members sitting on the other side know it is not being implemented. Even at the time of promotion, employees of these categories are being victimised. When they form an association, it is not recognised.

Finally, I would like to say about my State. Sir, I have been making for the last ten years a plea for grant of Statehood to the Union Territory of Pondicherry. I brought a Private Member's Bill in this House. The hon. Home Minister was kind enough to reply to the debate and he was sympathetic. But the hon. Home Minister's sympathy does not go to the extent of my getting relief as I wanted, because there are some bottlenecks. The bottlenecks are within the Government. It was almost decided that the concept of Union Territory should not be there. The power is with the Lt. Governor. The State Government which has been elected by the people, which is representing the will of the people has no say in the administration. Therefore, this issue was raised by me in this august House and it was also agreed to by the hon. Home Minister. These issues have not been discussed in the Address. The President's Address is general like the Address delivered by him in the previous year. Therefore, I submit that various issues like agriculture, infrastructure industry, basic necessities of the people, States' problems which have been daunting the nation, should have been addressed. Therefore, I submit that the President's Address should have contained more particulars which are wanted today by the people of this country. But these things are lacking in it. In spite of that—as a member of the party which is supporting this Government—I just support the Motion moved by Shrimati Kamla Sinha.

**SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (ASSAM):** Mr. Vice-Chairman, Sir, while generally supporting the Motion of Thanks to the President for his Address to the Members of both Houses in its joint sitting on the 20th February,

1997 I have to pinpoint some glaring omissions in the Address regarding problems of Assam and North-East States.

The entire State of

Assam is in turmoil for some years past. The Government of India is apparently trying to contain the so-called insurgency problem by deployment of security forces. While it has been admitted by the Chief of the army Staff and other military officers in charge of the security forces in the North-East and more particularly in Assam, the questions raised by the militants are political questions and the same have to be solved politically and that there is no military solution to it. There is no indication in the Address whether the Government of India treats the questions raised by the militants as political ones or they treat the questions as simple law and order questions capable of being solved by deployment of security forces. The Government of India declares from time to time that they are ready to talk with the militants, unconditionally but we do not find anything in the Address as to what concrete steps or initiatives have been taken for the purpose. Whether it is admitted by the Government or not, action by the security forces have resulted in excesses leading to unnecessary loss of lives, violation of human rights and a feeling of alienation of the people, which is a serious matter. The Address also is singularly silent about the large scale infiltration of people from neighbouring countries to the entire North-East Region, especially to Assam leading to apprehension in the minds of the people of being outnumbered with serious disturbances in the demographic, social and cultural pattern. There has been a widespread resentment and active opposition to the unabated infiltration causing law and order situation in some of the States. The matter will go out of control if prompt remedial measures to stop infiltrators are not taken to allay the fears of the people of this region.

There has been a discrimination in the matter of dealing with foreigners and in imposition of the IMDT Act in Assam

which makes detection and deportation of foreigners impossible. This has led to widespread resentment and the people demand that the said controversial Act be repealed and uniform measures in dealing with the question of foreigners be restored by taking recourse to the Foreigners Act.

In view of the mega scams all over the country involving thousands of crores of rupees and implicating persons in high places, the country expected that the problem should have been taken up with all seriousness and stringent measures should have been suggested in the Address.

While China is executing scores of economic offenders, specially people found guilty of misappropriating public funds, we, with our sense of highest regard and respect for human lives, cannot go to the extent China has gone. We can at least make the law of prevention of corruption more stringent. In order to make the Act effective, provisions should be made for speedier disposal of cases of corruption. In extreme cases, a penalty of deprivation of civil rights, including taking away the right to vote, should be imposed on persons who indulge in corruption, in violation of the oath of allegiance to the constitution taken by persons in high places.

The President's Address does not indicate anything to ensure transparency in Executive and bureaucratic actions. The provisions of the Official Secrets Act require amendment. In spite of Articles 73 and 74 of the Constitution, powers have not been transferred to the Panchayats, thereby hampering implementation of development works at the village level. Panchayats have to be conferred with financial and other powers to ensure decentralization of power to the grass-roots level. The Address is silent about the problem of massive unemployment. There is no indication of any measures to meet this challenging problem. In the absence of any industry worth the name in the region, and also in the absence of employment generating programmes, the

huge army of unemployed youth is bound to be a source of social upheaval and law and order problem. It would have been a matter of great satisfaction had the President's Address suggested positive programmes to meet the challenge of unemployment. With these words, I offer my gratitude to the President and also support the Motion of Thanks to the President's Address.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Mr. M.P. Abdussamad Samadani. You have promised to finish in five minutes.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): I will finish before that. Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks to the President's Address. I am going to refer to two, three points. I don't want to go into the details. I don't want to repeat the sentiments which have already been expressed by various hon. Members in their speeches. The law and order situation in the country is, to some extent, satisfactory. But, at the same time, crimes are increasing. Among these crimes, cruelty against women is also increasing. The moral decay is going to reach the dangerous point of making the life of woman insecure. The custodians of law and order are also contributing to this unfortunate state of affairs. In Kerala, recently in a Press conference, it was stated by a woman Member of the Assembly that one-third of the total crimes in the State in the past years, were committed by the policemen. That is the unfortunate situation existing in the country. So, the Central Government should take a serious note of this situation and take some suitable steps at the earliest to check tremendous cruelties and immoralities against women. Many factors are responsible for this state of affairs. There are not only political reasons but also cultural reasons which are responsible in creating this background.

Cinema, television, etc., are also playing an important role in this drama. Our attitude towards art has contributed much to the cultural degradation. It is a chal-

lenge to our civilisation which is our great heritage. As a result of the spreading of the seeds of immorality, the life of poor people is in danger. Therefore, while taking part in this serious debate, my request is that the Central Government should take some urgent action to protect the life and dignity of ladies and provide safe passage for ladies throughout the country.

Another important matter which I want to stress here is the negation of justice to the Backward Classes. Our Constitution has hailed the idea of reservation. But now this idea of reservation is challenged by various forces. Reservation for Backward Classes is a serious issue which deserves our attention. I am sorry to say that the Speech of the hon. President does not contain much in this regard. Various new forces are threatening the very spirit of reservation. The hewers of wood and rowers of boats are still denied their basic rights. To make equality and social justice a reality of our polity, we have to protect the system of reservation polity, we have to protect the system of reservation from new challenges. The hue and cry related to identifying the creamy layer cannot be allowed to destroy the spirit of reservation. The Central Government should take note of this. Here I remember a very important Bill called "The Bill for Protection of Reservation for the Backward Classes" passed by the Kerala Assembly. Actually, this is a model for other States also. The Central Government should also do something to protect the Bill already passed by the Government of Kerala. The Central Government should take urgent steps for the educational uplift of minorities and Backward Classes. Their legitimate demand for reservation in the field of education cannot be ignored. Reservation will strengthen our national integrity and also our communal harmony. In our multi-lingual, multi-racial and multi-religious polity reservation is a must to make equality a reality. Unity and diversity is interlinked with equality. The Constitution provides for job reservation to Back-

ward Class citizens, if they are not adequately represented in the Government services. Reservation is accepted as a safeguard for the minorities and weaker sections throughout the world.

The third and last point which I want to refer to is related to protection of civil liberties. It is an important part of a democratic society. In our country a number of people are still imprisoned under the dead law, TADA. (Time bell rings) .....Just one minute, Sir. TADA is still misused to harass innocent citizens.

Throughout the country TADA is mentioned as a symbol of terror and horror. Innumerable modes of persecution, which are unheard in the history of human rights violation, are used under TADA. Its misuse is very extensive. Even colonial Britishers did not enact a law containing such draconian provisions as that of TADA or anything resembling to that. It is the blackest of all black laws. It was enacted on 25th May, 1985 as a temporary law to prevent disruptive activities in terrorist-affected areas. Later this law itself became a means of terrorism. This situation still continues. This law was severely criticised by human rights organisations. It was also criticised in the two reports of the United Nations Organisation. During the period of its validity itself the concerned authorities had admitted that TADA was misused. Then what is the justification for its misuse after its validity is over? The Hitlerian Act is dead, but the Hitlerian actions are still continuing in its name. This is not an issue related to majority or minority. It is a national issue. It is high time that the citizens who are held under TADA should be set free. If anybody is to be tried, let him be brought before the common law of the country. protection of life and limbs is very important. Under a jungle law whose validity is already over an assault on the Indian system of justice is going on. It is an attack against the democratic decency. The Government cannot ignore the voice of civil liberty associations of the country against the injustice done to a number of innocent citizens in

jails. I cannot understand it. Why are Governments after Governments keeping mum? Why don't they respond to the nationwide opposition against this injustice? The United Front partners were active in fighting against TADA earlier. They had categorically promised that they would do justice to the TADA detenus. But they have not yet done anything in this regard. Power has become an opium for them also which has made them forget their own promises. I request the United Front Government to remember their own promises concerning TADA and justice to the TADA detenus at the earliest. I am reminded of a couplet of a famous poet Iqbal:

“ताही हलाम का यह बर्षा मज़ली है,  
कि साहिबे नज़रं निश कुव्वत है खतरनाक।”

I request the United Front Government not to be led by power, but do justice to the depressed classes.

Thank you.

SHRI W. ANGOU SINGH (MANIPUR): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. The Home Minister is sitting here. I am quite fortunate because the issue I am going to raise in my speech is related to the Home Ministry. Sir, the present United Front Government is functioning under the umbrella of the Common Minimum Programme. In a Conference of Chief Ministers held in July, 1996, it was decided to achieve seven basic minimum services. We have also supported and accepted these seven basic minimum services. Under these seven basic minimum services, the present United Front Government is committed to bridge the gap in the levels of development of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the minorities and to bring them on a par with the rest of the society, which has been clearly mentioned in the President's Address. But in actual practice, the minorities are totally neglected. I, being a representative of a minority community

of the North-East area feel that the officers belonging to our community are being ill-treated. Apart from that, different development programmes in the region are being neglected. For example, it has happened in the Delhi Police which comes under the Home Ministry. An IPS Officer, who belongs to the Union Territory cadre and who has been transferred from Arunachal Pradesh, has not been given any posting for more than five to six months. Later on he was posted as Director, Vigilance. But within a short span of time he was transferred to the Delhi Police. Since December, 1996, he has not been posted anywhere. This is the situation. I do not know why such kind of an ill-treatment and injustice is being done to an officer belonging to minority community of the North-East. Since the Delhi Police comes under the Home Ministry, I have written a letter about his posting to the Home Minister, but nothing has happened so far. If such a small matter is not looked into properly, what will be the feeling of the minority community? Simply mentioning it in the President's Address and simply paying a lip-service to the people of the minority communities and the Backward Classes is not going to serve the purpose. We have seen shouting for a PM's package for the North-East also like the one given to J&K. Our Prime Minister came and announced a package of Rs. 6100 crores. But in actual terms, this is nothing but only an adjustment towards the normal programmes of the States. We demand that the problems of the North-East be solved by paying special attention towards these states where the light of development has not reached. We don't say that the Government of India has not given funds for various programmes there. But what is happening in the North-East? If a house is on fire, we have to take immediate steps to put out the fire. If we wait for the fire brigade and not do something until it comes, the situation will worsen. So, I propose that there should be a Minister exclusively for the North-East region. The Government

should consider this. But this has not been mentioned in the President's Address. There is regional imbalance in India between the States and within the State itself. This imbalance is with regard to industrial and agricultural growth. In the hill areas of the North-East region, we have villages which have no roads. The major cause for concern in this regard is that these States are not likely to feel the positive impact of reforms, nor do they have the ability to transform themselves overnight into attractive tourist destinations. In addition to this, there are restrictions like the Inner Line Permit, which are imposed. In this way, the Central Government is playing the same role as that of the British regime. Hence, the region is lagging behind in socio-economic growth. In such a situation, a doubt arises in my mind: Is it the responsibility of the State alone to provide social and economic infrastructure which is required to create a suitable environment for growth? Insurgency started because of the negligence of the Central Government. In 1960 there was surplus. But the Centre did not meet the revenue-account expenditure of the State. This gave rise to discontentment. Discontentment breeds insurgency. All this insurgency problem started because of the attitude of the Central Government. Now, both the Centre and the States have deficit current accounts which compels them to borrow. Special attention needs to be paid to the North-East region by the Central Government in order to make up for lapses in the past. The report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs clearly mentions that the North-East region, comprising seven states, has been afflicted by insurgency due to different factors which include ethnic, linguistic, historic, economic and geographical factors. These insurgent groups have been aided and encouraged by countries from across the borders. But there is not a single line. There is not a single line about border development in the President's Address. The North-East

region has 1126 kilometres of international border line with China. It has 489 kilometres of border line with Bhutan and 1648 kilometres with Myanmar and 1187 kilometres with Bangladesh. These long border areas are left untouched even now. In order to control different untoward incidents which may disturb the law and order situation there and threaten the national integration of this country, border areas should be developed. Hence, this should be the prime programme of the present Government.

With a hope that the present U.F. Government will take immediate necessary steps, I now support the Motion of Thanks on the President's Address.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): श्री दारा सिंह चौहान। आपकी मेडन स्पीच है।

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चल रहे धन्यवाद प्रस्ताव पर आज मुझे सदन में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे तो कई दिन से इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मैं इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाके, पूर्वांचल और उसमें भी जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, आजमगढ़, उससे बिलांग करता हूँ। इस पूर्वांचल के विकास की बातें समय-समय पर होती रही हैं और आप भी जानते हैं कि अलग राज्य की बात भी हो रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जिन्हें कभी-कभी "किसान का बेटा" भी लोग कहते हैं, कि पूर्वांचल जो इस देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है, जैसे तो हम कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उस पूर्वांचल का सबसे बड़ा उद्योग वह खाद का कारखाना है जो गोरखपुर में स्थित है और उसके बारे में प्रधान मंत्री जी कई बार घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक यह मालूम नहीं है कि वह खाद का कारखाना चलेगा या नहीं, यह आज तक नहीं बताया जा सकता।

महोदय, आज आजादी के इतने दिन बाद भी भारत में, जो एक कृषि प्रधान देश है, एक तिहाई जमीन पर खेती होती है। आज भी इस देश में जितनी भी जमीन पर खेती होती है उससे दुगुनी जमीन बेकार पड़ी हुई है। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हम अपने देश में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे पास जमीन भी है, काम करने वाले लोग भी हैं लेकिन आज उन काम करने वाले लोगों को जमीन नहीं मिलती है। इस वास्ते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बेकार पड़ी हुई जमीनें हैं, वे उन लोगों को दे दी जाएं। आज सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। किस सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं? जो गरीब और मेहनतकश लोग हैं, जो अपना खून-पसीना ष्क करके, दूसरे के खेत में काम करके अपने पेट को भरते हैं, उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने आज तक खेत की मेड़ को देखा नहीं है, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि किस गरीब की बात महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में है? क्या उन गरीबों के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है? उनके लिए सरकार क्या करना चाहती है? आज शिक्षा की बात की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कुछ प्रदेशों को छोड़कर बाकी देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। वह गरीब आदमी जिसके बच्चे रात में भूखे पेट सो जाते हैं, वे शिक्षा कहां से ग्रहण करेंगे? आज हमारे खेतिहर मजदूरों के पास खुद की खेती नहीं है। वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हमारी जो यह सरकार है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, उन गरीबों के लिए क्या यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है? हमारी जो दो-तिहाई जमीन आज भी बेकार पड़ी हुई है, जो बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में है, अगर उसे गरीबी में बांट दिया जाए तो हमारे देश से यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। दिल्ली में जो रेलवे लाइन के किनारे गरीब लोग झोपड़-पट्टी बनाकर रहते हैं और किसी तरह से अपना पेट पालते हैं, वह सब आपको देखने को नहीं मिलता।

महोदय, हमारे पूर्वांचल के लोगों को जब काम नहीं मिलता है तो वे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े महानगरों में आ जाते हैं। इसके वितरित गांवों में जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है। आज भूमि-सुधार की बात होती है। जितनी भी सरकारें आईं, सब लोगों ने गरीबों की बात

की, भूमि-सुधार की बात की लेकिन आज तक भूमि-सुधार की कोई भी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। आज भी जो गरीब लोग हैं, जो शौह्यूल्ट कास्टस और शौह्यूल्ट ट्राईब्स के लोग हैं और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको जो भी पट्टा दिया गया है, उस पर उनको आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। उस पट्टे की जमीन आज भी मजबूत लोगों के कब्जे में है जो हजारों एकड़ भूमि के मालिक हैं, जो नंबर 2 की कमाई को बचाने के लिए बड़े-बड़े फर्मों के मालिक बने हुए हैं, जो टैक्स बचाने के लिए बड़े-बड़े फर्मों के मालिक बने बैठे हैं। उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

महोदय, इस देश में जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो श्रम करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके श्रम की पूजा नहीं होती है। चाहे वह मानसिक या जो या शारीरिक श्रम हो, श्रम करने वाले लोगों को इस देश में छोटा समझा जाता है। यह यहां की व्यवस्था रही है। आज जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गंदी नालियां साफ करने का काम करता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वह अपने बच्चों को उस काम में नहीं लगाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि श्रम करने वाले लोगों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस अभिभावक में उसका कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। डा० अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 45 में व्यवस्था की थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी लेकिन संविधान को जो दस्तावेज डा० अम्बेडकर ने हमें सौंपा था, जिसके आधार पर इस सदन की कार्यवाही हो हम चलाते हैं, उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। महोदय, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, किसी सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। जो आज भी वे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उनके मां-बाप के पास जमीन नहीं है, वे गरीब हैं, वे दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं तो वे अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से देंगे?

महोदय, आप जानते हैं कि शिक्षा एक बुनियादी चीज है। जब तक समाज में शिक्षित लोग नहीं होंगे, समाज का मनोबल नहीं बढ़ेगा। जिस समाज के अंदर शिक्षा नहीं होती है, वह समाज गुलाम हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने इन गरीबों के लिए तमाम कार्यक्रम बनाए लेकिन ईमानदारी से गरीबों के सामाजिक स्तर पर को, शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया है।

अगर ईमानदारी उनके अंदर होती, उनके अंदर ममता होती गरीबी समाज के प्रति जिसकी आज हम दुहाई देते हैं, तो निश्चित रूप से वह जो जमीन है, आज जो बड़े-बड़े समाएदार हैं, बड़े-बड़े जमींदार जिनके हाथ व कब्जे में जमीन है वह गरीबों में बांट करके उनके बच्चों की पेट की भूख मिटाई जा सकती है तथा इससे वह अपने बच्चों के शिक्षा का स्तर भी आगे बढ़ा सकते हैं दूसरे की बराबरी में। आज भी हमारे देश में ऐसे गरीब लोग हैं जिनके रहने का ठिकाना नहीं, जिनके बच्चे भरपेट भोजन भी नहीं पाते हैं तथा प्राइमरी शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं और देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, दून स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। जब प्रतियोगिता में शामिल करने की बात आती है तो दून में पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल जाता है। तो क्या मंशा है इस सरकार की? इस देश में रहने वाले तमाम समाज को चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी जाति-मजहब का हो सबको सम्मान मिले। ऐसे भी गांव हैं जहाँ स्कूल भी नहीं है, चूँकि वह बेचारे अशिक्षित समाज के लोग हैं। चूँकि आज ऐसे समाज में लोग हैं जिस बराबरी और जिस सम्मान की बात यह सरकार कहती है। मैं कहना चाहता हूँ उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भी समाज में ऐसे इंसान हैं जिनको इंसान का दर्जा नहीं, जीने का हक नहीं। आज मैं जानता हूँ जिस पूर्वांचल का मैं रहने वाला हूँ, आज भी जो शादी-विवाह के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी समाज में रहने वाले ऐसे लोग हैं, जब हम खाना खिलाते हैं और जो पत्तल बनाने का काम करते हैं उसे मूसर कहते हैं। जब हम खाना खाने के बाद पत्तल को फैंकते और उसमें जब कोई रोटी भूलकर चली जाती है तो उस रोटी को लेने के लिए कुत्ता दौड़ता है तथा उस रोटी को लेने के लिए मूसर का बेटा भी परेशान हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार क्या करना चाहती है इस समाज के लिए जिनको आज भी इंसानियत का दर्जा हासिल नहीं है।

चूँकि समय कम है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस नाते मैं वहां का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी यहां बीच में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता का जो माहौल है, आज वहां जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ मेरे जिले में हफ्तों पहले तीन मस्लाहों का मर्डर हो गया। आज भी आंखों के सामने 11 बजे दिन में जीप से सवारी खाली करके दो लोगों की हत्या कर दी गई। गाजीपुर में भी दो अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कर दी गई। जिस

दलित समाज के उत्थान की बात वह सरकार करती है, तो उस दलित उत्थान के लिए, शैक्ष्युल्ड कास्ट के लिए उनका सम्मान कैसे सुनिश्चित होगा। कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। आप भी जाते होंगे, उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी, पूरा प्रदेश जानता है जब उनकी सरकार थी और आज जिन लोगों का सम्मान आज प्रदेश में नहीं है, जिनकी इज्जत नहीं बच पाती है, आज हत्याएं और डकैती हो रही हैं, एक भी हत्या और डकैती नहीं हुई थी, सारे लोग अपने मान-सम्मान की जिंदगी जी रहे थे। आज भंडारी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भंडारी जी केन्द्र के नियंत्रण के बाहर दिखाई पड़ते हैं। उनके जो पेपर्स के माध्यम से बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आज इस सदन का उपयोग जहां हमारे देश के विकास में खर्च होना चाहिए आज सारे सदस्यों ने कुछ समय उत्तर प्रदेश पर चर्चा करने के लिए लिया। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का जो लां एंड आर्दर है, आज जो अराजकता का माहौल है, जो अधिकारी है वे तो बात नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो दलित उत्थान की बात करती है। कुछ सदस्यों को कल मैं सुन रहा था।

शैक्ष्युल्ड कास्ट के लिए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए हरिजन शब्द का अद्बोधन किया है। मैं सदन के माध्यम के उनको बताना चाहता हूँ कि संविधान में हरिजन कोई शब्द नहीं है। हमारे यादव जी ने भी हरिजन शब्द का उद्बोधन किया था तो संविधान से हरिजन शब्द नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इस शब्द पर ध्यान देते हुए...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): दारु सिंह जी, एक मिनट रुकिए। पांच बज गए हैं और एक वक्ता और है इसलिए अगर हाऊस सहमत है तो हम आज इसे समाप्त करेंगे। दारु सिंह जी आगे बोलिए।

श्री दारु सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, तमाम चीजें हैं जिस गरीबी और बेरोजगारी की बात की जाती है, जिस सिंचाई की बात की जाती है, प्री सिंचाई की बात की जाती है, प्री बोरींग स्कीम की बात की जाती है, मैं गेलवार, जाफरपुर गांव का रहने वाला हूँ और किसान का बेटा हूँ और जानता हूँ कि आज भी किसान को प्री बोरींग स्कीम की जो सुविधा दी जाती है, वह बी०डी०ओ० के, सेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगता है। बैंक में उसकी फाइल जाती है लेकिन बैंक में बिना घूस लिए

उसको ऋण नहीं दिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहती है?

आज मिट्टी का तेल है। गरीब अपने घर में दीया भी नहीं जला पाता है और आज पूरे हिन्दुस्तान में तमाम घोटाले नज़र आ रहे हैं। कितने घोटाले हैं इस देश में, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज इन घोटालों की वजह से पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान के मान-सम्मान को ठेस लगी है। एक-दो सवाल आए थे लोक सभा में बहस और टेलीफोन कनेक्शन के बारे में। मैं इनका इच्छुक नहीं हूँ मान्यवर लेकिन इस भ्रष्टाचार के कारण कितने घोटाले हैं, चाहे आयुर्वेद घोटाला हो या चारा घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, आज उन्हीं के नाते पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के सम्मान को बट्टा लगा है। टेलीफोन और गैस कनेक्शन महत्वपूर्ण विषय नहीं है लेकिन यह कह कर कि गैस और टेलीफोन कनेक्शन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसके कारण गैस और टेलीफोन के कनेक्शन को खत्म कर दिया गया है, निश्चित रूप से भारत में रहने वाली जनता के सामने एक प्रश्न-चिन्ह लग गया है कि जो हमारे मैनबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे सदन के सदस्य हैं, अगर भ्रष्टाचार में वे न होते तो शायद स्पीकर साहब समाप्त न करते। यह भी एक अहम सवाल है। मैं इसका इच्छुक नहीं हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने मुझे पहली बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): बहुत-बहुत धन्यवाद। Shri R.K. Kumar. He is the last speak.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Sir, thank you very much. Probably, I am the last speaker. The time is five and the receptivity will be very low. Even though Lord May in his "Parliamentary practice" has said that on the Queen's Address you can speak on anything under the sun, I will briefly restrict myself to one or two things and will take only five minutes. What does the President's Address contain? It contains the background of the coalition, and a pat on the back for the coalition—of course, it has been written by the Government and mouthed by the

President—as to how cohesively the coalition has been working. Secondly, it contains the state of the economy. Thirdly, it contains our relations with certain foreign countries. Sir, I would like to speak briefly on these three points.

Sir, first of all, I would like to say something on the state of the coalition, and the background of the coalition. The coalition was not born to prove whether they are secular or non-secular because, at the time when election results were coming, two leaders who formed part of the coalition in Tamil Nadu went on the television to say this: one leader said, "I will take the call from the party which secures the largest number of seats", the other leader said, "They are not untouchables." Then suddenly, the bogie of secularism came up. What happened in between?

What happened in between? Because the single largest party formed the Government, and it filled up all important portfolios, the people who said, "We will take a call, they are not untouchables", suddenly thought that they somehow had to stop the non-secular forces from forming the Government.

This is now the coalition was formed, not serve the people but to stop one single largest party. Secondly, after forming the coalition Government, something legitimate had to come out as to what for the Government was being formed. So, the Common Minimum Programme was written, published, announced and discussed. The President's address repeats mostly the Common Minimum Programme. What has been achieved out of the Common Minimum Programme? We do not know, we are yet to see. Sir, as far as the cohesiveness of the coalition is concerned—the hon. Home Minister is here—enough has been said about U.P. and I do not want to repeat. But briefly, I would mention one or two other points. On the issue of Almatti, on the issue of Cauvery, We are all very much concerned how the

Cauvery dispute is being handled. There does not seem to be any give and take among the coalition partners. This is so in many other things. Even one particular bank scam. one Member says something and the hon. Finance Minister asks her to withdraw the charge, and she refuses to withdraw it saying that her party is being forced to be in the coalition. This is the type of cohesiveness with which it is working. I do not want to say much more on that.

On the state of the economy, the President's address glosses over a very very minimal increase in agricultural production, as compared to the earlier year which itself was a bad performance. Had it been compared with the earlier year to that, we could have understood and then it would be a negative performance. We have also been talking about the infrastructure development. Except setting up the Infrastructure Development Finance Company, no concrete plan has been disclosed as to how fast and how well the infrastructure is going to be developed. Sir, I do not want to comment much on the foreign affairs because this is an area where Pranabji knows much. I am very naive on that. This is the third point in the President's Address. Except that, there is nothing. I would like to say that we are not against the coalition. Let the coalition work. But let it work more cohesively. As there is nothing in this President's Address on all these matters, and how effectively, how cohesively the coalition is going to work, I have to regret that I have to oppose this motion. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 6th March, 1997.